



करेंट अफेयर्स

माध्य प्रदेश

अप्रैल

(संग्रह)

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

मध्य प्रदेश	4
➤ मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयन	4
➤ प्रदेश में होगी स्टेम सेल थैरेपी आधारित बोनमेरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना	4
➤ मध्य प्रदेश की सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी	5
➤ मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट-2022'	5
➤ मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना	6
➤ देश में सर्वाधिक ब्रूसेल्ला टीकाकरण मध्य प्रदेश में	7
➤ 'मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना, 2022' का शुभारंभ	7
➤ 'USha अवार्ड'	8
➤ देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत	8
➤ टीकम जोशी	9
➤ नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ	10
➤ ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र	10
➤ जल अभिषेक अभियान की शुरुआत	11
➤ महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती	11
➤ मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी के बिजनेस ट्रांसफार्मेशन का क्रियान्वयन करेगी 'एक्सेंचर'	11
➤ चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड	12
➤ स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को स्कॉच सिल्वर अवार्ड	13
➤ ऊर्जा साक्षरता में मिलेगा राज्य एवं जिला स्तरीय पुरस्कार	13
➤ राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार	14
➤ राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला एसएचजी के आउटलेट का शुभारंभ	14
➤ इंदौर को स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में मिले 6 अवार्ड	15

नोट :

➤ लाडली लक्ष्मी उत्सव	15
➤ नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश	16
➤ लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये दतिया ज़िले को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार	16
➤ मध्य प्रदेश के लिये 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत	17
➤ 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस	17
➤ सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड	17
➤ भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय पर हुआ वेबिनार	18
➤ 'माँ तुझे प्रणाम योजना'	19
➤ 'मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह' में विभूतियों का सम्मान	19
➤ नीति आयोग की नवोन्वेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री	20
➤ मध्य प्रदेश 'आयुष्मान भारत' में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम	20
➤ मलेरिया नियंत्रण में मध्य प्रदेश को मिला सम्मान	21
➤ मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय	21
➤ मध्य प्रदेश में मवेशी को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर होगी कार्रवाई	22
➤ इंदौर में तीन दिवसीय 'एमपी ऑटो-शो-2022'	22
➤ तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा	23
➤ ऊर्जा विभाग और केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के बीच ऋण एवं अनुदान के लिये अनुबंध हस्ताक्षरित	23

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश से 3 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय तीरंदाजी टीम में चयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी की खिलाड़ी मुस्कान किरार, रागिनी मार्को तथा सृष्टि सिंह का भारतीय तीरंदाजी टीम में चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- तीनों ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जबलपुर स्थित राज्य तीरंदाजी अकादमी के कोच रिचपाल सिंह सलारिया के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- मुस्कान किरार ने एशियाई खेलों (2018) में रजत पदक, रागिनी मार्को ने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप (मैड्रिड, स्पेन) में मिश्रित स्पर्धा में स्वर्ण पदक तथा सृष्टि सिंह ने इटली में विश्व विश्वविद्यालय खेलों में भाग लेने के साथ राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किया है।
- मुस्कान किरार मूलरूप से जबलपुर की निवासी हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में एकलव्य पुरस्कार और वर्ष 2019 में विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- उल्लेखनीय है कि भारतीय टीम इस वर्ष पाँच विश्व कप (विभिन्न चरणों) और एशियाई खेलों (चीन) में भाग लेगी।

प्रदेश में होगी स्टेम सेल थैरेपी आधारित बोनमेरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना

चर्चा में क्यों ?

1 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बताया कि प्रदेश में स्टेम सेल थैरेपी आधारित बोनमेरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- बोनमेरो ट्रांसप्लांट एवं पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना मध्य प्रदेश के चार मेडिकल कॉलेज भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर और रीवा में की जाएगी।
- प्रदेश में बच्चों की जेनेटिक बीमारियाँ, जैसे- सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, थैलीसीमिया तथा कैंसर जैसे- ल्यूकीमिया, मल्टीपल माईलोमा, नॉन हॉजकिंस लिंफोमा के उपचार के लिये बोनमेरो ट्रांसप्लांट यूनिट की स्थापना की जाएगी।
- प्रथम चरण में गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में 6 बिस्तरीय बोनमेरो ट्रांसप्लांट यूनिट एवं 24 बिस्तरीय पीडियाट्रिक कैंसर यूनिट की स्थापना की जाएगी।
- इस यूनिट के माध्यम से विश्वस्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें स्वयं के (ऑटोलॉग्स) स्टेम सेल ग्राफ्टिंग एवं अन्य व्यक्ति के (एलोजेनिक) बोनमेरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
- बच्चों में सिकल सेल एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एवं थैलीसीमिया जैसी जेनेटिक बीमारियों के कारण बच्चों के संक्रमित बोनमेरो को निकालकर दूसरे व्यक्ति का स्वस्थ बोनमेरो ट्रांसप्लांट किया जाएगा।
- पीड़ित बच्चों के बोनमेरो को ट्रांसप्लांट करने के लिये प्राथमिक डोनर बच्चों के भाई-बहन होते हैं, जिनका बोनमेरो मैच करने की संभावना 25 प्रतिशत से अधिक होती है।

- कैंसर जैसे ल्यूकीमिया, मल्टीपल माईलोमा, नॉन हॉजकिंस लिंफोमा से पीड़ित मरीजों में उनके ही स्टेम सेल को निकालकर ऑटोलॉग्स स्टेम सेल ट्रांसप्लांट किया जाएगा। पीड़ित मरीज के ही स्टेम सेल को निकालकर उसको क्रायो प्रिज़र्व किया जाएगा। फिर ऑटोलॉग्स ट्रांसप्लांट की जाएगी।

मध्य प्रदेश की सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

3 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष सकल राजस्व प्राप्ति 57,720 करोड़ रुपए थी, जो इस वर्ष 67,609 करोड़ रुपए हो गई है।

प्रमुख बिंदु

- वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य शासन की बेहतर कर नीति, वित्तीय अनुशासन और करदाताओं को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराने के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021-22 में सकल राजस्व प्राप्तियों में 17.13% की बढ़ोतरी हुई है।
- वाणिज्यिक कर विभाग के अनुसार जीएसटी का लक्ष्य 21,600 करोड़ रुपए का था, जिसके सापेक्ष 22,206.01 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। इस प्रकार प्राप्तियों में 102.81 प्रतिशत की उपलब्धि रही।
- नॉन जीएसटी करों में 16,540 करोड़ रुपए का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 16,745.35 करोड़ रुपए प्राप्ति कर 101.24 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की गई।
- पंजीयन और स्टांप शुल्क में 7,400 करोड़ रुपए के लक्ष्य के सापेक्ष 8,164.85 करोड़ रुपए प्राप्त कर 110.34 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की गई।
- आबकारी में 10,340 करोड़ रुपए लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्ति 10,386 करोड़ रुपए रही, जो 100.45 प्रतिशत है।

मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट-2022'

चर्चा में क्यों ?

4 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंडिया हैबिटेड सेंटर, नई दिल्ली में 'मध्य प्रदेश सुशासन एवं विकास रिपोर्ट-2022' के पहले संस्करण का विमोचन किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है, जो मध्य प्रदेश की अनूठी शासन प्रथाओं को सामने लाता है, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने और व्यापक निगरानी शामिल हैं।
- मध्य प्रदेश सरकार के स्वायत्त निकाय, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान (AIGGPA) भोपाल द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है।
- रिपोर्ट में प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई कई अहम पहल, जिनमें स्कूल ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप, समाधान ऑनलाइन, सीएम हेल्पलाइन आदि की स्थापना शामिल हैं।
- 'मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट-2022' (MPSDR) में कुल 12 अध्याय हैं, जिन्हें पाँच पार्ट में बाँटा गया है।
- इसके पहले खंड में दो अध्याय सुशासन पर हैं, जिनमें 15 साल के दौरान प्रदेश में सुशासन की विशिष्टताओं का जिक्र किया गया है।
- दूसरे खंड में कोरोना काल और उसके असर का जिक्र है। साथ ही महामारी के प्रबंधन और इससे हुए बदलाव व विकास की चर्चा भी की गई है।

- रिपोर्ट के तीसरे खंड के पहले अध्याय में बताया गया है कि राज्य कृषि क्षेत्र में देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा अग्रणी रहा है। प्रदेश खाद्यान्न का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, बागवानी फसलों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक तथा पोषक-अनाज में पाँचवा सबसे बड़ा उत्पादक है।
- तीसरे अध्याय में ही उद्योग और व्यापार का जिक्र एवं विश्लेषण किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों में विशेष फोकस के साथ वित्तीय समावेशन पर जोर दिया गया है।
- पाँचवा अध्याय जैव विविधता और पारंपरिक ज्ञान के दोहन पर है। ये जैव विविधता की भूमिका और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के महत्त्व पर चर्चा करता है।
- 6वें अध्याय में आयुष क्षेत्र तथा 7वें अध्याय में शहरी विकास की चर्चा है।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में बताया कि-
 - ◆ प्रदेश की विकास दर (19.7 प्रतिशत) देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6 प्रतिशत का योगदान दे रहा है। सकल घरेलू उत्पाद में बीते दशक में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
 - ◆ बिजली का उत्पादन 5 हजार मेगावाट से बढ़ाकर 21 हजार मेगावाट तक पहुँचाया गया।
 - ◆ कई बार कृषि कर्मण अवार्ड प्राप्त करने वाले मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को गेहूँ उपार्जन में पीछे छोड़ दिया है।
 - ◆ प्रदेश में एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी बनाई गई है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजनाओं से लाभान्वित सिंचाई रकबा 43 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है।
 - ◆ मध्य प्रदेश पहला राज्य है, जिसने पब्लिक सर्विस गारंटी कानून बनाया। समय पर सेवाएँ न देने वाले लोग दंडित किये जाते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना

चर्चा में क्यों ?

5 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 'मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना' के संशोधन को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- अब योजना में सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम में सम्मिलित पात्र प्रति कन्या के नाम से 55 हजार रुपए स्वीकृत किये जाएंगे।
- इस राशि में से 6 हजार रुपए की राशि सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजन करने हेतु आयोजनकर्ता निकाय को देय होगी एवं 38 हजार रुपए की सामग्री तथा 11 हजार रुपए का एकाईट पेयी चेक कन्या को उपहार के रूप में आयोजनकर्ता निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- श्रम विभाग के मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक हेतु विवाह सहायता योजना को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में समाहित किया जाएगा।
- कार्यक्रम के लिये अधिकृत संस्था सामूहिक विवाह का आयोजन शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद तथा ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत ही आयोजनकर्ता होंगे। अन्य किसी संस्था द्वारा कराए जा रहे सामूहिक विवाह इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होंगे।
- सामूहिक कन्या विवाह/निकाह कार्यक्रम का सुचारु रूप से आयोजन सुनिश्चित किये जाने हेतु जिला एवं निकाय स्तरीय समितियों का गठन जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से किया जाएगा। इन समितियों में वरिष्ठ शासकीय अधिकारी भी सदस्य होंगे।
- जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से जिला कलेक्टर द्वारा जिले के प्रत्येक निकाय के लिये सामूहिक विवाह एवं निकाह हेतु 2-2 तिथियों का वित्तीय वर्षवार कैलेंडर जारी होगा। इस कैलेंडर का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे इच्छुक जोड़ों द्वारा समय पर आवेदन किया जा सके।
- आवेदन की प्रक्रिया पूर्वानुसार रहेगी, जिसके तहत वर-वधू को सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम के आयोजन की तिथि से कम-से-कम 15 दिवस पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त आवेदन करना होगा।

देश में सर्वाधिक ब्रूसेल्ला टीकाकरण मध्य प्रदेश में

चर्चा में क्यों ?

6 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने बताया कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चलाए गए ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 1 जनवरी से 31 मार्च, 2022 तक ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया। इसमें 4 से 8 माह की गो-भैंस वंशीय बछियों का टीकाकरण कराया गया। मध्य प्रदेश ने 17 लाख 41 हजार 970 टीकाकरण की जानकारी ईनॉफ पोर्टल पर दर्ज कराई है, जो राष्ट्र में सर्वाधिक है।
- इसके अलावा प्रदेश में 2 करोड़ 76 लाख 63 हजार 968 गो-भैंस वंशीय पशुओं को यूआईडी टैग लगाए गए हैं। इनका पंजीकरण भी ईनॉफ पोर्टल पर किया गया है। यह संख्या भी देश में सर्वाधिक है।
- उल्लेखनीय है कि देश में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में ब्रूसेल्ला टीकाकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।
- ब्रूसिलोसिस रोग गो-भैंस वंशीय पशुओं में प्रजनन संबंधी बीमारी है, जो ब्रूसिलोसिस एबॉर्टस जीवाणु के कारण होती है। रोग के लक्षणों में बुखार, गर्भावस्था के अंतिम चरण में गर्भपात, बाँझपन, हीट में देरी, लेक्टेसन में बाधा आदि से बछियों की हानि और दूध उत्पादन में कमी होती है।
- 4 से 8 माह की गो-भैंस वंशीय बछियों का जीवनकाल में एक बार टीकाकरण कर उन्हें ब्रूसिलोसिस रोग से बचाया जा सकता है। यह रोग पशुओं से मनुष्यों में भी फैल जाता है। इस रोग के प्रभाव से पुरुष एवं स्त्रियों में प्रजनन संबंधी समस्या हो सकती है। इस रोग को किसी उपचार के अभाव में टीकाकरण द्वारा ही रोका जा सकता है।

'मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना, 2022' का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के कटनी जिले के स्लीमनाबाद में 'मुख्यमंत्री बिजली बिलों से राहत योजना, 2022' का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- कोविड काल की अवधि के प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के एक किलोवाट तक भार वाले पात्र घरेलू कनेक्शन पर 31 अगस्त, 2020 तक का 6400 करोड़ रुपए से अधिक के बिजली बिल माफ कर दिये गए हैं, जिसे राज्य सरकार भरेगी।
- जिन उपभोक्ताओं ने समाधान योजना, 2021 के अंतर्गत स्थगित राशि के विरुद्ध भुगतान किये हैं, उन्हें भी आगामी बिलों में समायोजित किया जाएगा।
- कटनी जिले के 5929 लाख 44 हजार रुपए के बिल इस योजना में माफ होंगे।
- गौरतलब है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के अंतर्गत 362 वितरण केंद्रों पर समारोहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित कर शिविर आयोजित किये गए।
- मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि राज्य शासन द्वारा जारी 'मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना, 2022' के अंतर्गत कंपनी द्वारा कार्यक्षेत्र के सभी 16 जिलों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित कर पहले दिन ही लगभग 18 हजार 587 उपभोक्ताओं से आवेदन प्राप्त कर 33 करोड़ 15 लाख से अधिक राशि माफ कर प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया है।
- कंपनी ने कहा है स्थायी रूप से विच्छेदित उपभोक्ताओं को योजना का लाभ लेने एवं पुनः कनेक्शन संयोजित कराने के लिये विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार औपचारिकताएँ पूर्ण करना अनिवार्य होगा। पात्र उपभोक्ता योजना में मिलने वाले लाभ को 1 अप्रैल, 2022 के बाद जारी देयकों में देख सकेंगे।

‘USha अवार्ड’

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश राज्य शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) में नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं जिलास्तरीय ‘USha अवार्ड’ देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- दोनों अवार्ड 6 श्रेणियों में दिये जाएंगे। राज्यस्तरीय अवार्ड का चयन प्रबंध संचालक ऊर्जा विकास निगम की अध्यक्षता में गठित कमेटी और जिलास्तरीय अवार्ड का चयन जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाएगा।
- अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण, जैसे- पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य BEE स्टार रेटेड उपकरण और प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- ‘USha अवार्ड’ प्रदेश में प्रतिमाह ऊर्जा साक्षरता अभियान में सर्वाधिक पंजीयन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, प्रतिमाह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम जिले को, ऊर्जा संरक्षण संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन, जो ऊर्जा बचत प्रमाणित करते हैं, को दिया जाएगा।
- इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग और संस्थान को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी को राज्यस्तरीय पुरस्कार दिया जाएगा।
- ‘USha अवार्ड’ जिला अभियान में सर्वाधिक पंजीयन एवं सर्टिफिकेशन करने वाले सबसे उत्कृष्ट स्कूल, कॉलेज और शासकीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार मिलेगा। जिले में ऊर्जा दक्षता अपनाने वाले सबसे उत्कृष्ट व्यक्तियों और संस्थाओं को प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा।
- पंजीयन कराने वाले सबसे उत्कृष्ट किसान और गृहिणी को भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार की एक अन्य श्रेणी विशेष उपलब्धि के लिये भी निर्धारित की गई है।
- किसान का चयन उनके द्वारा ऊषा अभियान से जुड़ने और कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, जैसे- ड्रिप इरीगेशन, सोलर पंप आदि सम्मिलित किये जा सकते हैं। गृहिणी का चयन उनके द्वारा ऊषा अभियान से जुड़ने और ऊर्जा बचत के लिये उन्नत सुझाव के आधार पर किया जाएगा।
- अन्य विशेष उपलब्धि श्रेणी में जिलास्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान पर किसी भी व्यक्ति, संस्थान, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि के उत्कृष्ट प्रदर्शन, विशेष सहयोग अथवा उपलब्धि शामिल होगी।

देश में पहली बार मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

7 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन कार्यालय का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस मिशन से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा शिक्षा एवं चिकित्सकीय उपचार की नवीनतम तकनीक, नवाचार एवं शोध के विभिन्न आयामों को मध्य प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों तक पहुँचाया जाएगा।
- इस मिशन में विभिन्न आयामों पर कार्य किया जाएगा। देश-विदेश के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों (शासकीय एवं निजी) के साथ शिक्षा, अनुसंधान और उपचार के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।
- इस मिशन के तहत चिकित्सकीय छात्रों एवं चिकित्सकों के लिये ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज एक्सचेंज, एक्पोजर विजिट प्रोग्राम आदि कार्यक्रम तैयार किये जाएंगे। नॉलेज एक्सचेंज इंटरैक्टिव डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिससे चिकित्सकीय छात्र एवं चिकित्सक अपने अनुभवों, रिसर्च कार्यों एवं अन्य नवाचारों को एक-दूसरे से डिजिटल रूप से साझा कर सकेंगे।

- नवीनतम तकनीकों (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस- AI) एवं गूगल तथा माइक्रोसॉफ्ट आधारित आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सकीय व्यवस्था क्षेत्र में किया जाएगा।
- इस मिशन के अंतर्गत ही शासकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों, जैसे- शंकर नेत्रालय चेन्नई, टाटा कैंसर हॉस्पिटल मुंबई, फोर्टिस गुडगाँव एवं अपोलो हॉस्पिटल के साथ सुपर स्पेशिअलिटी शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल रोबोटिक्स के उपयोग, चिकित्सा पद्धति और गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये चिकित्सकीय एवं शैक्षणिक आदान-प्रदान किया जाएगा।
- अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के साथ बोनमेरो ट्रांसप्लांट एवं एमोरी यूनिवर्सिटी के साथ संक्रामक बीमारियों के उपचार एवं चिकित्सा शोध के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा।
- देश एवं विश्व के विभिन्न विधाओं के ख्यातिप्राप्त चिकित्सकों द्वारा प्रदेश के मरीजों की जटिल बीमारियों के उपचार के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किया जाएगा, जिसमें हेल्थ कैंप, चिकित्सा परामर्श सुविधा एवं शल्य चिकित्सा की व्यवस्था चिकित्सा महाविद्यालय के हॉस्पिटल में की जाएगी।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित कर प्रदेश के चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों के साथ ही प्रदेश से चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर देश-विदेश के प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों में कार्य करने वाले चिकित्सकों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन कर जोड़ा जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में किये जा रहे शोध-कार्यों एवं नवाचारों को डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जाएगा।
- AI तकनीक के उपयोग से टीबी, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, दिल की बीमारी, कैंसर, जैसे- लीवर, प्रोस्टेट, ब्लैडर, पेट के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर एवं थायरॉइड बीमारी की प्राथमिक स्तर पर पहचान तथा AI आधारित डिजिटल पैथोलॉजी से मरीजों की जाँच के आयामों को विकसित किया जाएगा।
- मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में मरीजों के जाँच एवं उपचार के डाटा को एकत्रित कर सॉफ्टवेयर आधारित मशीन लर्निंग से जाँच और उपचार के विभिन्न एल्गोरिद्म (Algorithm) को तैयार किया जाएगा, जिससे चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों को मरीजों के इलाज और उपचार में मदद मिल सकेगी।
- मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मशीन के माध्यम से नवीन मेडिकल डिवाइस के शोध एवं विकास के लिये गांधी मेडिकल कॉलेज में इनक्यूबेशन सेंटर को विकसित किया जाएगा, जिससे चिकित्सकों एवं चिकित्सा छात्रों को नए चिकित्सा उपकरणों को मरीजों की आवश्यकता के अनुसार शोध करने और विकसित करने का अवसर मिल सकेगा।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल के छात्रों को विशिष्ट ट्रेनिंग देकर उनके कार्यक्षेत्र में दक्षता प्रदान करने के लिये स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा।
- मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन को वैश्विक पटल पर स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, विश्व बैंक सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को भी साथ में जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

टीकम जोशी

चर्चा में क्यों ?

9 अप्रैल, 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने टीकम जोशी को थिएटर के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया।

प्रमुख बिंदु

- भोपाल के टीकम जोशी ने अभिनय में विशेषज्ञता के साथ 2001 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से स्नातक पूर्ण किया।
- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग ने 30 मार्च को जोशी को एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा (एमपीएसडी) का निदेशक नियुक्त किया है।
- जोशी के अतिरिक्त अर्जुन सिंह धुर्वे को भी लोक एवं जनजातीय नृत्य के लिये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड प्रदान किया गया है।

नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने गांधी मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम से मेडिकल नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की, साथ ही ब्रोशर का विमोचन भी किया।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि जीएमसी का ऑडिटोरियम वातानुकूल बनेगा। सभी मेडिकल कॉलेजों में विद्यार्थियों की सुविधा के लिये रि-क्रिएशन सेंटर स्थापित किये जाएंगे। हमीदिया के इमरजेंसी विभाग को नंबर-वन बनाया जाएगा।
- इस नॉलेज एक्सचेंज प्रोग्राम के जरिये एक-दूसरे की बौद्धिक क्षमता का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके जरिये इंस्टीट्यूट सहित विशेषज्ञ डॉक्टर्स से भी एमओयू किया जा रहा है, जो अपनी विधाओं के जरिये ज्ञान को साझा करेंगे।
- चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने युवा डॉक्टर्स से एमपी गव और नॉलेज शेयरिंग पोर्टल के जरिये ज़्यादा-से-ज़्यादा जुड़ने की अपील की।
- आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवड़े ने बताया कि 13 बिंदुओं पर आधारित नॉलेज शेयरिंग मिशन सेल की स्थापना की गई है। मध्य प्रदेश के नवाचारों का फायदा पूरे देश को मिले, इस दिशा में कार्य किये जा रहे हैं।
- आईआईटी इंदौर के साथ मेडिकल इन्व्यूबेशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। यह सेंटर शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा।

ग्रामीण परिवहन नीति के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ शीघ्र

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने ग्रामीण परिवहन नीति के क्रियान्वयन पर अधिकारियों से चर्चा के दौरान बताया कि प्रस्तावित नवीन परिवहन नीति के तहत रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट (आरटीसी) मॉडल को 1 मई, 2022 से आगामी 6 माह तक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विदिशा जिले में क्रियान्वित किये जाने के लिये राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिये गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि ग्रामीण अंचलों में सुगम एवं सस्ती लोक परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के लिये परिवहन विभाग द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल के सहयोग से प्रदेश में नवीन ग्रामीण परिवहन नीति प्रस्तावित की गई है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने पर पूरे प्रदेश में इसे रोलआउट किये जाने की योजना है।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विगत दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था के पुनः सुचारु संचालन के लिये परिवहन नीति लाने के निर्देश दिये थे।
- ग्रामीण परिवहन के लिये विदिशा जिले में कुल 76 ग्रामीण मार्गों को चिह्नित किया गया है, जिनकी कुल लंबाई 1513 किमी. है। इन ग्रामीण मार्गों एवं इनके आसपास 546 ग्राम स्थित हैं, जिससे 4 लाख 70 हजार ग्रामीण जनसंख्या प्रस्तावित नीति से लाभान्वित होगी।
- प्रस्तावित ग्रामीण परिवहन नीति के तहत मार्ग पर 7+1 से 20+1 बैठक क्षमता के वाहनों के संचालन की अनुमति होगी तथा इस ग्रामीण परिवहन सेवा के लिये संचालित वाहनों पर मध्य प्रदेश मोटरयान अधिनियम, 1991 के तहत देय मासिक मोटरयान कर में पूरी छूट दी जाएगी।
- इसके अलावा परिवहन सेवा के रूप में निरंतर 6 माह तक संचालित वाहनों के संचालकों द्वारा उक्त संचालन से अर्जित किये गए रूरल ट्रांसपोर्ट क्रेडिट के विरुद्ध निर्धारित मूल्यानुसार प्रोत्साहन राशि आगामी 6 माह में वाहन संचालक को प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के तहत इच्छुक वाहन संचालक वैध प्रपत्र होने पर जिला परिवहन कार्यालय में आकर अथवा परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर निर्धारित 76 ग्रामीण मार्गों में से किसी एक मार्ग पर अथवा आपस में जुड़े हुए एक से अधिक मार्गों पर वाहन संचालन के लिये परमिट प्राप्त करने का आवेदन कर सकते हैं।

जल अभिषेक अभियान की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले की गैरतगंज तहसील के कहुला ग्राम में आयोजित जल संसद में जल अभिषेक अभियान की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 52 जिलों के 5 हजार अमृत सरोवर का वर्चुअल शुभारंभ और पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान में 10 हजार कार्यों का भी शुभारंभ किया।
- मुख्यमंत्री ने जलशक्ति अभियान की आयोजना का विमोचन भी किया। उन्होंने जल संचयन के लिये अपने खेतों में तालाब बनवाने वाले 551 जल-योद्धाओं में से तीन जल-योद्धाओं को सम्मानित किया।
- उल्लेखनीय है कि इस वर्ष प्रदेश में 5000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। इनका कार्य जून माह तक अथवा अगले वर्ष मार्च माह तक पूरा हो जाएगा। जल-संरक्षण के लिये बड़ी संख्या में छोटी-छोटी जल-संरचनाओं के संरक्षण का कार्य भी किया जाएगा।

महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती

चर्चा में क्यों ?

11 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दमोह में पिछड़ा वर्ग कल्याण के जननायक महात्मा ज्योतिबा फुले की 195वीं जयंती समारोह में विभिन्न घोषणाएँ कीं।

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब हर साल महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर शासकीय कर्मचारियों के लिये ऐच्छिक अवकाश रहेगा।
- पिछड़ा वर्ग सहित गरीबों, दलितों के उत्थान तथा बालिकाओं की शिक्षा के लिये महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी धर्मपत्नी सावित्री बाई फुले ने महत्वपूर्ण कार्य किये अतः उनके विचारों को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार उनकी जीवनी को शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करेगी।
- दमोह जिले के लिये स्वीकृत एक सी.एम. राइज स्कूल का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब प्रत्येक वर्ष महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती को अलग-अलग स्थान पर धूमधाम से मनाया जाएगा। उन्होंने दमोह जिले की बटियागढ़ ग्राम पंचायत को नगर पंचायत का स्वरूप दिये जाने की भी घोषणा की।
- महात्मा ज्योतिबा फुले का पूरा जीवन महिलाओं, गरीबों और किसानों के लिये सघर्ष में बीता। उन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति पैदा की और विधवा विवाह की मुहिम चलाई। यही कारण रहा कि मुंबई में वर्ष 1888 में हुई किसान सभा में उन्हें 'महात्मा' की उपाधि दी गई।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विगत तीन वर्षों के मध्य प्रदेश महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़ा वर्ग सेवा राज्य पुरस्कार वितरित किये। वर्ष 2017-18 के लिये डबरा के डॉ. हुकुम सिंह कुशवाह, वर्ष 2018-19 के लिये उमरिया के बी.आर. सातपुते तथा वर्ष 2019-20 के लिये रीवा के आर.एन. पाटिल को 2-2 लाख रुपए के चेक एवं प्रशस्ति-पत्र भेंट किये गए।

मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिंग कंपनी के बिजनेस ट्रांसफार्मेशन का क्रियान्वयन करेगी 'एक्सेंचर'

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश पावर जेनेरेटिंग कंपनी द्वारा बिजनेस ट्रांसफार्मेशन और डिजिटाइजेशन के लिये इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) क्रियान्वयन के लिये एक्सेंचर (Accenture) का चयन किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश पावर जेनेरेशन कंपनी की ईआरपी परियोजना की शुरुआत गत दिवस एक समारोह में हुई।
- एक्सेंचर एक वैश्विक प्रबंधन परामर्श और पेशेवर सेवा फर्म है, जो रणनीति, परामर्श, डिजिटल, प्रौद्योगिकी और संचालन सेवाएँ प्रदान करती है।
- एक्सेंचर फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनी है। विश्व की अग्रणी आईटी कंपनियों में से एक 'एक्सेंचर' को पावर जेनेरेशन सेक्टर में ईआरपी क्रियान्वयन का वृहद् अनुभव है।

चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य लोगों को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- समारोह में सम्मानित होने वाली अन्य विभूतियों में पंडवानी लोकशैली की गायिका तीजन बाई, राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम, पूर्व महापौर इंदौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़, आविष्कारक बनवारी लाल चौकसे, पूर्व लोकसभा सांसद डॉ. भागीरथ प्रसाद, भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ कलापनि कोमकली, सेवा धर्म आश्रम उज्जैन के संस्थापक सुधीर भाई गोयल, संचालक दैनिक भास्कर कार्प लिमिटेड गिरीश अग्रवाल, भारतीय सिने अभिनेता पीयूष मिश्रा, उद्यमी मनन दीक्षित, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री दिव्यंका त्रिपाठी, चेयरमैन दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड दिलीप सूर्यवंशी, ध्रुपद गुरु अभिजीत सुखदाणें, वक्ता एवं लेखक आर्या चावड़ा, चेयरमैन आर.साई. लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रोहित सिंह तोमर, प्रदेश की पहली महिला पर्वतारोही मेघा परमार, वरिष्ठ पत्रकार न्यूज एंकर (ए.बी.पी.) विकास भदौरिया, प्रेसीडेंट केंप प्रियंका द्विवेदी, प्रबंध संचालक नर्मदा हेल्थ ग्रुप डॉ. रेणु शर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रकाश जैन, फाउंडर येलो डिजी मयूर सेठी और कार्यपालिक सचिव ज्ञान गंगा ग्रुप रजनीत जैन आदि शामिल हैं।
- चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी (IFIE) संस्था, भारत सरकार द्वारा देश में चिह्नित कुल 115 आशावादी जिलों में गांधीवादी मूल्यों (स्वच्छता), सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास को अपने सकारात्मक प्रयासों से बढ़ावा देने वाले राजनेता, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्यमियों को दिया जाता रहा है।
- इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी संस्था प्रतिवर्ष भारत में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार का आयोजन करता है। इस अवार्ड को आम तौर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या भारत के एक प्रमुख व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। पुरस्कार विजेताओं का चयन न्यायपूर्ति केजी बालकृष्णन (भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और NHRC के पूर्व अध्यक्ष) की अध्यक्षता में शीर्ष संवैधानिक जूरी पैनल द्वारा किया जाता है।
- इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकॉनमी संस्था भारत सरकार से मान्यता प्राप्त (80G, 8A के अनुरूप), गैर-लाभकारी कंपनी है, जो महात्मा गांधी के मूल्यों को बढ़ावा देने वाले 115 आकांक्षात्मक जिलों सहित ग्रामीण भारत की महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण के लिये समर्पित है। नंदन झा चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार के अध्यक्ष हैं। इसकी स्थापना 2011 में हुई थी।
- चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश पुरस्कार साहस, सामुदायिक सेवा और समावेशी सामाजिक विकास के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये एक राज्य पुरस्कार है। यह पुरस्कार महिला स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर शुरू किया गया है। पुरस्कार विजेताओं का चयन न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा (सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश) की अध्यक्षता में संवैधानिक जूरी के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को स्कोच सिल्वर अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

12 अप्रैल, 2022 को देश में अपनी तरह के सबसे पहले एवं सबसे आधुनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी स्मार्ट मीटर का विशाल प्रोजेक्ट संचालित करने वाली मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी को देश का प्रतिष्ठित स्कोच सिल्वर अवार्ड प्राप्त हुआ है।

प्रमुख बिंदु

- इस अवार्ड के लिये देश की विभिन्न बिजली कंपनियाँ, राज्यों के ऊर्जा विभाग, बैंक, शासकीय सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्थाएँ और तकनीकी संस्थाएँ आदि शामिल थीं।
- पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी ने श्रेष्ठ सेवाओं, योजना के कार्यों की स्कोच टीम के साथ सर्वोत्तम प्रस्तुति, वोटिंग एवं अन्य मापदंडों को पूरा करते हुए सिल्वर अवार्ड हासिल किया है।
- गौरतलब है कि महु (इंदौर) शत प्रतिशत स्मार्ट मीटर वाला मध्य प्रदेश का पहला शहर है, वहीं इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, खरगोन आदि में अब तक पौने तीन लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।
- 2003 में स्थापित स्कोच (SKOCH) अवार्ड, उन लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है, जो भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिये अतिरिक्त प्रयास करते हैं।

ऊर्जा साक्षरता में मिलेगा राज्य एवं ज़िला स्तरीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में मध्य प्रदेश शासन ने ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) में सक्रिय भाग लेने वालों को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं ज़िला स्तरीय अवार्ड देने का निर्णय लिया है।

प्रमुख बिंदु

- राज्य स्तरीय अवार्ड के लिये 6 श्रेणियाँ निर्धारित की गई हैं। प्रतिमाह अभियान में पंजीयन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम ज़िले को 'उत्कृष्ट ज़िला पंजीयन' की श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह प्रतिमाह सर्टिफिकेशन संख्या के आधार पर प्रदेश के प्रथम ज़िले को 'उत्कृष्ट ज़िला सर्टिफिकेशन' श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा।
- ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतों और अन्य भवन, जो प्रमाणित ऊर्जा बचत प्रदर्शित करेंगे, को 'ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अपनाने वाली उत्कृष्ट इमारतें' श्रेणी में पुरस्कृत किया जाएगा।
- 'उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाएँ' श्रेणी में प्रदेश स्तर पर अभियान के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय, विभाग, उद्योग आदि को पुरस्कृत किया जाएगा।
- ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ज़िला अक्षय ऊर्जा अधिकारी श्रेणी में प्रदेश में सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अक्षय ऊर्जा अधिकारी को पुरस्कृत किया जाएगा।
- प्रतिमाह 'सबसे उत्कृष्ट कॉलेज' श्रेणी में डिग्री, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज का चयन किया जाएगा।
- ऊर्जा साक्षरता अभियान UShA में सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला शासकीय कार्यालय को भी पुरस्कृत किया जाएगा।
- ऊर्जा दक्षता अपनाने वाला सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति/संस्था श्रेणी में ज़िला स्तर पर ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार दिया जाएगा।
- 'ऊर्जा साक्षरता अभियान' उत्कृष्ट किसान श्रेणी में UShA से जुड़ने और कृषि क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता अपनाने की प्रामाणिक जानकारी देने पर किसान को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह ऐसी गृहिणी, जो UShA से जुड़ी हैं, किसी शासकीय नौकरी में नहीं हैं और उसने ऊर्जा बचत के लिये उन्नत सुझाव दिया है, को पुरस्कृत किया जाएगा।

- इसके अलावा अन्य विशेष उपलब्धि श्रेणी में पुरस्कार जिला स्तर पर ऊर्जा साक्षरता अभियान में किसी भी व्यक्ति, संस्थान, शासकीय कार्यालय, स्कूल, कॉलेज आदि के उत्कृष्ट प्रदर्शन, विशेष सहयोग एवं उपलब्धि के लिये दिया जाएगा।
- UShA अवार्ड-प्रदेश एवं UShA अवार्ड-जिला से संबंधित सारी जानकारी मध्य प्रदेश UShA विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अवार्ड प्रदेश में स्थित चयनित श्रेणियों के स्कूल, कॉलेज, कार्यालय, संस्थान और व्यक्ति विशेष को ही दिया जाएगा। अवार्ड के रूप में ऊर्जा दक्ष उपकरण (पंखे, स्टार रेटेड एलईडी ट्यूबलाइट, बल्ब और अन्य बीईई-स्टार रेटेड उपकरण) एवं प्रमाण-पत्र दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये मध्य प्रदेश शासन ने जन-भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विश्व में अनूठा ऊर्जा साक्षरता अभियान (UShA) प्रारंभ किया है। इसमें लोगों को ऊर्जा की बचत, लाभ और संरक्षण की जानकारी मोबाइल एप, वेब पोर्टल आदि द्वारा प्रशिक्षण और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से दी जा रही है।

राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2022 को तीन दिवसीय राष्ट्रीय वनमाली कथा पुरस्कार समारोह भोपाल स्थित रवींद्र भवन में संपन्न हुआ।

प्रमुख बिंदु

- इस साहित्य पुरस्कार की स्थापना वनमाली सृजन पीठ और रवींद्रनाथ ठाकुर विश्वविद्यालय (आरएनटीयू) द्वारा हिन्दी लेखक जगन्नाथ प्रसाद चौबे वनमाली की स्मृति में की गई है।
- गौरतलब है कि इन पुरस्कारों की घोषणा 14 अप्रैल, 2022 को हुई थी, जिसके तहत वनमाली कथा शीर्ष सम्मान प्रो. धनंजय वर्मा को तथा वनमाली राष्ट्रीय कथा सम्मान गीतांजलिश्री को दिया गया। इन दोनों पुरस्कारों में प्रत्येक को एक-एक लाख रुपए की नकद राशि, शॉल और एक प्रशस्ति-पत्र दिया गया।
- इसके अतिरिक्त वनमाली कथा मध्य प्रदेश सम्मान भोपाल के प्रसिद्ध लेखक हरि भटनागर को, वनमाली युवा कथा सम्मान बेंगलुरु के युवा लेखक चंदन पांडे को, वनमाली कथा आलोचना सम्मान दिल्ली के वैभव सिंह एवं वनमाली साहित्य पत्रिका सम्मान दिल्ली से प्रकाशित मासिक पत्रिका कथादेश को दिया गया।
- इस वर्ष शामिल दो नई श्रेणियों में पहला, वनमाली प्रवासी भारतीय कथा सम्मान लंदन की दिव्या माथुर को और दूसरा, वनमाली विज्ञान कथा सम्मान दिल्ली के विज्ञान लेखक देवेन्द्र मेवाड़ी को दिया गया। इन पुरस्कारों में 51,000 रुपए का नकद पुरस्कार, शॉल और एक प्रशस्ति-पत्र दिया गया।

राजा भोज एयरपोर्ट पर महिला एसएचजी के आउटलेट का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

17 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राजा भोज एयरपोर्ट, भोपाल में महिला स्व-सहायता समूहों को प्रमोट करने के उद्देश्य से एयरपोर्ट पर आवंटित आउटलेट का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- इस महिला स्व-सहायता समूह आउटलेट का शुभारंभ भारत सरकार के अवसर कार्यक्रम के तहत किया गया है।
- गौरतलब है कि सभी एयरपोर्ट पर स्थानीय उत्पादों को बिक्री के लिये उपलब्ध कराने और स्थानीय लोगों को रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने के लिये यह योजना शुरू की गई है।
- इसका उद्देश्य महिलाओं व शिल्पकारों की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के साथ ही उन्हें उपयुक्त अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) संचालित हवाई अड्डों में 100-200 वर्ग फीट के निर्धारित क्षेत्र में स्वयं-सहायता समूहों को एक-एक कर 15 दिनों की अवधि के लिये स्थान का आवंटन किया जा रहा है।

इंदौर को स्मार्ट सिटी कॉन्फ्रेंस में मिले 6 अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

18 अप्रैल, 2022 को गुजरात के सूरत में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कांटेस्ट में इंदौर ने विभिन्न कैटेगरी में 6 अवार्ड हासिल किये।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ' इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स कांटेस्ट, 2020 ' में विभिन्न थीम में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्मार्ट सिटीज को अवार्ड वितरित किये।
- इस कॉन्टेस्ट में मध्य प्रदेश ने स्टेट अवार्ड में दूसरा स्थान हासिल किया है। इसके अलावा भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर ने भी अवार्ड जीते हैं।
- इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कांटेस्ट (आईएसएसी), 2020 की सभी प्रतियोगिताओं में ओवरऑल विनर के रूप में इंदौर के साथ सूरत को चुना गया है, जबकि जबलपुर को तीसरा स्थान दिया गया है।
- कल्चर थीम में इंदौर और चंडीगढ़ को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। इसी थीम पर डिजिटल म्यूजियम बनवाने पर ग्वालियर को तीसरा स्थान मिला है। इंदौर को हेरिटेज के बेहतर संरक्षण पर यह अवार्ड मिला है।
- साथ ही इंदौर को स्वच्छता थीम पर म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिये तिरुपति के साथ संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया।
- इंदौर को इकोनॉमी थीम पर कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मेकैनिज्म के लिये, बिल्ट एनवायरनमेंट थीम पर छप्पन दुकान के लिये, इनोवेशन अवार्ड में कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग मेकैनिज्म तथा सिटी अवार्ड में इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से ओवरऑल विनर का अवार्ड दिया गया।
- अर्बन एनवायरनमेंट थीम में संयुक्त रूप से भोपाल और चेन्नई विजेता घोषित हुए। भोपाल को क्लीन एनर्जी में उल्लेखनीय कार्य करने पर यह अवार्ड मिला है। सिटी अवार्ड में राउंड-1 में जबलपुर को तीसरा और राउंड-3 में सागर को दूसरा स्थान मिला है।

लाडली लक्ष्मी उत्सव

चर्चा में क्यों ?

19 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों को राज्य स्तरीय लाडली लक्ष्मी उत्सव के लिये सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण करने के निर्देश दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन 2 मई को राजधानी भोपाल में किया जाएगा। इसमें लाडली लक्ष्मी योजना की हितग्राही बालिकाओं को आमंत्रित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम में बालिकाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देने और 'माँ तुझे प्रणाम योजना' में चयनित बालिकाओं को देश की सीमाओं की भ्रमण यात्रा के लिये रवाना किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त प्रदेश भर में 3 से 11 मई की अवधि में पंचायत स्तर पर भी उत्सव आयोजित होगा। इसमें विभिन्न जिलों में स्थानीय स्तर पर विभिन्न गतिविधियों, जैसे- बालिकाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, फॉलिक एसिड टेबलेट्स वितरण, रंगोली एवं अन्य स्पर्द्धाओं के साथ खेलकूद आदि से लाडली लक्ष्मियों को जोड़ा जाएगा।
- गौरतलब है कि प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल, 2007 से बालिकाओं के सशक्तीकरण हेतु किया गया था। इस योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों, जैसे- लिंगानुपात में सुधार, बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर के उन्नयन और स्वास्थ्य में सुधार आदि की प्राप्ति में यह अत्यधिक उपयोगी सिद्ध हुई है।

नेशनल कैंसर ग्रिड की सदस्यता लेने वाला पहला राज्य बनेगा मध्य प्रदेश

चर्चा में क्यों ?

20 अप्रैल, 2022 को चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा नवाचार की श्रृंखला में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये शुरू किये गए मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन के अंतर्गत चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल के संचालक के साथ वर्चुअल बैठक की।

प्रमुख बिंदु

- बैठक में मध्य प्रदेश को नेशनल कैंसर ग्रिड से जोड़ने एवं मेडिकल नॉलेज शेयरिंग मिशन में टाटा मेमोरियल अस्पताल के साथ एमओयू करने पर निर्णय लिया गया।
- इससे प्रदेश के कैंसर रोगियों को बेहतर उपचार के साथ ही कैंसर शोध को प्रोत्साहन एवं प्रदेश के चिकित्सकों को उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा।
- गौरतलब है कि नेशनल कैंसर ग्रिड (एनसीजी) के तहत देश में 266 सेंटर्स संचालित किये जा रहे हैं, जहाँ कैंसर के उपचार एवं शोध को लेकर कार्य किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त ग्रिड द्वारा एक डिजिटल पोर्टल भी प्रारंभ किया गया है, जिसमें मरीज अपनी मेडिकल रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी अपलोड कर एक्सपर्ट डॉक्टरों से परामर्श कर सकते हैं।

लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये दतिया ज़िले को मिला प्रधानमंत्री पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दतिया ज़िला प्रशासन को पोषण अभियान में जनभागीदारी को बढ़ावा देने और लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिये प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में दतिया ज़िले के कलक्टर संजय कुमार ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश कैडर के 3 अन्य अधिकारियों को भी पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से नवाजा गया।
- दतिया ज़िले में जनभागीदारी के माध्यम से पोषण अभियान में 'मेरा बच्चा अभियान' की शुरुआत की गई। अभियान में कुपोषित माँ और बच्चों की पहचान कर उन्हें कुपोषण से सुपोषण कार्यक्रम में शामिल किया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में कम वजन, टिगनापन और शारीरिक अपक्षय को दूर करना और महिलाओं में खून की कमी का उपचार करना है। इसके साथ ही ज़िले में 'पोषण मटका' थीम में कुपोषित बच्चों के परिवारों को खाद्यान्न सहयोग देने के लिये भी समुदाय को प्रेरित किया गया।
- इंदौर ज़िले के कलक्टर मनीष सिंह को 'स्वच्छ इंदौर अभियान' के लिये नागरिक-सरकारी इंटरफेस के लिये पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार, 2020 से सम्मानित किया गया।
- मध्य प्रदेश एमएसएमई के संचालक विशेष गढ़पाले को दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिये सरकार और नागरिक के बीच अलग-अलग इंटरफेस के लिये एक सॉफ्टवेयर विकसित करने हेतु पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार, 2019 से सम्मानित किया गया है।
- इसी क्रम में मध्य प्रदेश के आईएस अधिकारी अजय तिकी, जो वर्तमान में केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग में सचिव पद पर प्रतिनियुक्ति पर हैं, को संपत्ति दस्तावेज एवं कार्यों आदि के पंजीकरण के लिये 'वन नेशन-वन सॉफ्टवेयर' एप्लीकेशन विकसित करने के नवाचार के लिये पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार, 2021 दिया गया।

मध्य प्रदेश के लिये 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत

चर्चा में क्यों ?

21 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के पशुपालन एवं डेयरी मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा प्रदेश में 4 करोड़ 6 लाख पशुधन के मान से 406 चलित पशु चिकित्सा इकाई स्वीकृत की गई हैं।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण योजना में वर्ष 2021-22 में भारत सरकार द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई का नवीन घटक शामिल किया गया है। योजना में प्रति एक लाख पशुधन पर एक चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित की जाएगी।
- चलित पशु चिकित्सा इकाई का वाहन पूर्णतः आधुनिक उपकरणों और स्टाफ से सुसज्जित रहेगा। वाहन में एक पशु चिकित्सक, एक पैरावेट और एक वाहन चालक सह-सहायक रहेगा। इसके अलावा वाहन में पशु चिकित्सा, लघु शल्य चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान, रोग अन्वेषण से संबंधित आवश्यक उपकरण स्थापित रहेंगे। प्रचार-प्रसार के लिये प्रोजेक्टर, स्पीकर आदि भी लगाया जाएगा।
- वाहन में उपलब्ध आवश्यक मानव संसाधन, औषधि, वाहन के लिये पीओएल एवं रख-रखाव आदि के लिये प्रति वर्ष 18 लाख 72 हजार रुपए प्रति चलित पशु चिकित्सा इकाई का प्रावधान किया गया है। इसमें 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश रहेगा।
- वाहन, वाहन की साज-सज्जा, पशु चिकित्सा के लिये आवश्यक उपकरण, प्रचार-प्रसार उपकरण और फेब्रीकेशन के लिये भी 16 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। यह राशि 100 प्रतिशत केंद्रांश पर आधारित है।
- चलित पशु चिकित्सा इकाई के लिये कॉल सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। कॉल सेंटर में कॉल ऑपरेटर एवं पशु चिकित्सक की नियुक्ति की जाएगी। सेंटर के लिये भी 60 प्रतिशत केंद्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश राशि का प्रावधान किया गया है।

48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस

चर्चा में क्यों ?

22 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस का देश की पुलिस व्यवस्था में दो नजरिये से महत्वपूर्ण योगदान है।
- पहला समान चुनौतियों से निपटने के लिये देश भर की पुलिस के बीच तालमेल और दूसरा अपराधियों से दो कदम आगे रहने के लिये तकनीक का इस्तेमाल होगा।
- पुलिस विज्ञान कॉन्ग्रेस एक सामान्य रणनीति और तालमेल पर चर्चा करने और काम करने के लिये आदर्श मंच है, जिसकी बैठकें बीपीआरएंडडी (BPR&D) के तत्वावधान में आयोजित की जाती हैं।
- उन्होंने कहा कि पुलिस विभागों में 10 वर्षीय पुलिस रणनीति और वार्षिक समीक्षा की प्रथा को संस्थागत बनाया जाना चाहिये, क्योंकि अब ऐसे अपराध हो रहे हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, राज्यों में पुलिस के बीच समन्वय, राज्य के बाहर पुलिस के बीच समन्वय और प्रौद्योगिकी को आत्मसात् किये बिना लड़ना संभव नहीं है।

सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2022 को प्रयागराज स्थित मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आयोजित 19वाँ सीएसआई-एसआईजी अवार्ड समारोह में एमपी टेंडर्स पोर्टल ने परियोजना श्रेणी में वर्ष 2021 के लिये प्रशंसा का राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित 'सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस' अवार्ड प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- 19वाँ 'सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस' अवार्ड 2021 निविदाओं के लिये 'प्रशंसा का पुरस्कार' के रूप में मध्य प्रदेश सरकार ई-प्रोक्वोरमेंट सिस्टम एमपीएसईडीसी हेतु मील का पत्थर है।
- ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के लिये नोडल एजेंसी के रूप में एमपीएसईडीसी की भागीदारी के साथ वर्ष 2006 में कार्य शुरू किया गया था। यह उपलब्धि मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (एमपीएसईडीसी) के लिये दूरदर्शी परियोजना साबित हुई है।
- एमपीएसईडीसी ने न्यूनतम मानवीय भागीदारी के साथ फुलप्रूफ कार्यक्रम के लिये स्थिर समाधान बनाए हैं। संस्था ने पारदर्शिता, आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढाँचा और मजबूत टीम से इस सफलता को प्राप्त किया है।
- संस्था का लक्ष्य अपने भागीदारों को मूल्य-आधारित सेवाएँ देने, अच्छे परियोजना प्रबंधन विचारों को अपनाने, लगातार प्रशिक्षण, एक डाटा विश्लेषण डैशबोर्ड सुविधा और फर्म को अपने लक्ष्यों तक पहुँचने में मदद के लिये अपने सभी हितधारकों पर ध्यान केंद्रित करना है।
- संस्था ने अपनी परियोजना को आसान बनाने के लिये नवीनतम तकनीकी विकास को लागू किया है। साथ ही डाटा एनालिटिक्स को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए विषमताओं का लाभ उठाकर और समस्याओं के मूल कारण का पता लगाने में मदद करके सुधार किया है।
- उल्लेखनीय है कि सीएसआई एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है, जो कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ ई-गवर्नेंस में किये गए नवाचारों को स्वीकार करने के लिये दिया जाता है।

भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय पर हुआ वेबिनार

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट और विश्व की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग में से एक भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय पर वेबिनार आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

इस वेबिनार में देश और प्रदेश के गाइड, पुरातत्त्वविद् तथा इतिहास प्रेमियों ने हिस्सा लिया।

- वेबिनार में सेंट्रल इंडिया के रीजनल गाइड भोपाल के अजय सिंह चौहान ने बताया कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग में 4 कलर (लाल, सफेद, हरा और पीले) का उपयोग किया गया है। ये सभी कलर पत्तियाँ, पत्थर, हेमेटाइट आदि प्राकृतिक स्रोतों से बनाये गए हैं।
- भीमबेटका में नृत्य और संगीत, बाँडी आर्ट, आखेट और पशुओं को चित्रित किया गया है। इस प्रकार की पेंटिंग्स को पिक्टोग्राफ कहा जाता है।
- भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय में मानव जीवन की यात्रा चित्रित की गई है, जिसमें जीवन की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियाँ, पशु, आखेट, जंगल में उपयोगी चीजें एकत्रित करना आदि दिखाया गया है।
- उल्लेखनीय है कि भीमबेटका रॉक पेंटिंग और आश्रय भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर रॉक साइट है। यह प्रागैतिहासिक रॉक पेंटिंग और रॉक शेल्टर के लिये बहुत लोकप्रिय है।
- आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के अनुसार भीमबेटका की रॉक पेंटिंग 30 से 35 हजार वर्ष पुरानी है। प्रसिद्ध पुरातत्त्वविद् विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957-58 में नागपुर की यात्रा के दौरान विंध्य पर्वत श्रेणी में भीमबेटका की खोज की थी।
- हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने भीमबेटका से एक फॉसिल की खोज की है, जो करीब ढाई करोड़ वर्ष पुराना है। इस प्रकार के फॉसिल यूक्रेन, रूस और चीन में भी मिले हैं।

‘माँ तुझे प्रणाम योजना’

चर्चा में क्यों ?

23 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश की खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि कोविड काल के बाद ‘माँ तुझे प्रणाम योजना’ को पुनः शुरू किया जा रहा है। इस वर्ष योजना में पहली बार प्रदेश की ‘लाडली लक्ष्मियाँ’ देश की सीमा की यात्रा करेंगी।

प्रमुख बिंदु

- सशक्त भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के सपने को साकार करने के लिये युवाओं में देश की सीमाओं की सुरक्षा के प्रति जागृति लाने, राष्ट्र के प्रति समर्पण और युवाओं को सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों के प्रति आकर्षित करने के उद्देश्य से ‘माँ तुझे प्रणाम योजना’ की शुरुआत की गई है।
- मंत्री ने बताया कि 2 से 11 मई तक चलने वाले ‘लाडली लक्ष्मी उत्सव’ में 2 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 200 लाडली लक्ष्मियों को हरी झंडी दिखाकर बाघा बॉर्डर की यात्रा के लिये रवाना करेंगे।
- इस यात्रा से किशोरियों में न सिर्फ देश भक्ति की भावना जागृत होगी, बल्कि वे भविष्य में देश की सेवा कर स्वयं को आत्मनिर्भर बनाने में भी सफल होंगी।
- उल्लेखनीय है कि खेल एवं युवा कल्याण विभाग की ‘माँ तुझे प्रणाम योजना’ में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से चयन कर युवाओं को विभिन्न समूहों में देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भ्रमण के लिये ले जाया जाता है।
- सीमावर्ती भूमि में शहीदों को युवाओं द्वारा अपने निवास क्षेत्र से ले जाए गए जल से श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। युवाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र के रहवासियों की मदद से पशुपालन, कृषि व्यवसाय, उद्योग-धंधे, सिंचाई सुविधाएँ, भौगोलिक विशेषताएँ, सांस्कृतिक रीति-रिवाज, मान्यताएँ, त्योहार आदि का भी अध्ययन किया जाता है।
- वर्ष 2013 से प्रारंभ माँ तुझे प्रणाम योजना में अब तक प्रदेश के 12 हजार 672 युवाओं को लेह-लद्दाख, कारगिल-द्रास, आर.एस.पुरा, बाघा-हुसैनीवाला, तनोत माता का मंदिर, लोंगोवाल, कोच्चि, बीकानेर, बाड़मेर, नाथूला दर्रा, पेट्रापोल, तुरा, जयगाँव, अंडमान निकोबार एवं कन्याकुमारी कीयात्रा कराई गई है।
- खेल एवं युवा कल्याण विभाग की इस योजना में चयनित युवाओं को गृह निवास का यात्रा किराया, दैनिक भत्ता, आवास, भोजन, स्थानीय यातायात व्यवस्था, रेल आरक्षण व्यवस्था, ट्रेक सूट, टी-शर्ट और किट बैग उपलब्ध कराए जाते हैं।

‘मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह’ में विभूतियों का सम्मान

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मध्य प्रदेश प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ‘मध्य प्रदेश रत्न अलंकरण समारोह’ में विभिन्न विभूतियों को सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्यपाल ने इस अलंकरण समारोह में मध्य प्रदेश नवरत्न सम्मान से देश के प्रसिद्ध पत्रकार पद्मश्री आलोक मेहता, परम विशिष्ट सेवा मेडल (सेवानिवृत्त) एयर मार्शल प्रदीप पद्माकर बापट, पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्माता रूमी जाफरी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्राध्यापक लोकेंद्र त्रिवेदी, भारत सरकार द्वारा औद्योगिक जगत् में लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित संजीव सरन, लघु एवं वृत्त चित्र निर्माता-निर्देशक देवेन्द्र खंडेलवाल, वरिष्ठ समाजसेवी निर्मल दास नारंग, नृत्यांगना (कोरियोग्राफर) डॉ. टीना देवले तांबे, कवि एवं संपादक डॉ. सुधीर सक्सेना को सम्मानित किया।
- राज्यपाल ने डॉ. लक्ष्मी शर्मा (साहित्य एवं कला), डॉ. ए.के. द्विवेदी (होम्योपैथी चिकित्सा), डॉ. वैभव चतुर्वेदी (मानसिक चिकित्सा), डॉ. ममता सिंह, सुरेश सिंह भदौरिया, डॉ. दीपति सिंह हाड़ा (चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा), डॉ. डेविश जैन (शिक्षा-उद्योग एवं कृषि), हरनीत कौर राना (शिक्षा), अवधेश दवे (उच्च शिक्षा), राजकुमार साबू (उद्योग एवं व्यापार), इंजीनियर अमित ओझा (गणित शिक्षा) एवं समाज सेवी मनोज नंदकिशोर पांचाल को प्रतिभा सम्मान से अलंकृत किया।

- गौरतलब है कि मध्य प्रदेश प्रेस क्लब की स्थापना 18 अप्रैल, 1992 को हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष स्व. एल.एन. वर्मा थे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष डॉ. नवीन आनंद जोशी हैं तथा महासचिव भाई नितिन वर्मा एवं उपाध्यक्ष महेंद्र शर्मा हैं।
- मध्य प्रदेश प्रेस क्लब संस्था सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न वर्कशॉप और सेमिनार का आयोजन करती रहती है। यह आयोजन भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

नीति आयोग की नवोन्वेषी कृषि पर राष्ट्रीय कार्यशाला में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में नीति आयोग द्वारा नवोन्वेषी कृषि पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वर्चुअली शामिल हुए।

प्रमुख बिंदु

- प्रथम-सत्र नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. रवि कुमार की अध्यक्षता में हुआ। राज्यों में प्राकृतिक खेती पर हुए प्रथम तकनीकी-सत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वार्ड.एस. जगन मोहन रेड्डी ने भी वर्चुअली अपने विचार रखे।
- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिये प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये ग्राम स्तर तक वातावरण बनाने और इसमें किसानों की सहायता करने के लिये राज्य सरकार कई कदम उठा रही है।
- मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। प्रारंभिक रूप से प्रत्येक जिले के 100 गाँव में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिये विशेष गतिविधियाँ संचालित की जाएँगी। वर्तमान खरीफ की फसल से प्रदेश के 5,200 गाँव में प्राकृतिक खेती की गतिविधियाँ आरंभ होंगी।
- वातावरण-निर्माण के लिये प्रदेश में मई माह में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में कृषि से जुड़े विभागों के अधिकारियों के लिये राज्यस्तरीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। अब तक प्रदेश के 1 लाख 65 हजार किसानों ने प्राकृतिक खेती में रुचि दिखाई है।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हरित क्रांति के लिये किसानों को रासायनिक खाद पर सब्सिडी और अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती अपनाने के लिये किसानों को प्रोत्साहन देना और सहयोग करना आवश्यक है।
- प्राकृतिक खेती के लिये देसी गाय आवश्यक है। देसी गाय से ही प्राकृतिक खेती के लिये आवश्यक जीवामृत तथा धनजीवामृत बनाए जा सकते हैं। प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों को देसी गाय रखने के लिये 900 रुपए प्रति माह अर्थात् 10 हजार 800 रुपए प्रतिवर्ष उपलब्ध कराए जाएँगे। साथ ही, प्राकृतिक कृषि किट लेने के लिये किसानों को 75 प्रतिशत राशि सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी।
- प्राकृतिक खेती के मार्गदर्शन के लिये प्रत्येक विकासखंड में 5 पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की सेवाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। प्रत्येक गाँव में किसान मित्र और किसान दीदी की व्यवस्था भी होगी, जो प्राकृतिक खेती के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं और मास्टर ट्रेनर को मानदेय भी दिया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश प्राकृतिक खेती की दृष्टि से उपयुक्त है, यहाँ जनजातीय बहुल 17 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में परंपरागत रूप से रासायनिक खाद का उपयोग नहीं होता है।

मध्य प्रदेश 'आयुष्मान भारत' में शिकायतों के निवारण में देश में प्रथम

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के 2021-22 के प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश ने शिकायत निवारण में 86 अंक स्कोर प्राप्त कर 'आयुष्मान भारत' योजना में शिकायतों के निवारण को लेकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रमुख बिंदु

- मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने वर्ष 2021-22 के प्रगति प्रतिवेदन में शिकायत निवारण प्रणाली के तहत प्रदेश में 67 चिकित्सालयों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में अर्थ-दंड अधिरोपित कर एक करोड़ 57 लाख रुपए की वसूली की गई।
- इस योजना में 140 हितग्राहियों से प्राप्त शिकायतों के आधार पर 59 लाख 2 हजार रुपए बैंक खातों के माध्यम से वापस करा कर निःशुल्क उपचार के उद्देश्य को पूर्ण किया गया।
- आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के पात्र हितग्राहियों को पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हो रही हैं। योजना में पात्र हितग्राहियों को एक हजार शासकीय और निजी चिकित्सालयों से 5 लाख रुपए तक का उपचार प्रति परिवार प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाया जा रहा है।

मलेरिया नियंत्रण में मध्य प्रदेश को मिला सम्मान

चर्चा में क्यों ?

25 अप्रैल, 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मलेरिया दिवस पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश को मलेरिया नियंत्रण में उल्लेखनीय कार्य के लिए 'सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन' से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2015 की स्थिति में 25 जिलों में प्रति हजार आबादी पर एक-से-अधिक मलेरिया के प्रकरण पाए जाते थे, जो वर्ष 2021 में घटकर .03 प्रति हजार हो गए हैं।
- मध्य प्रदेश में अब एक भी ऐसा जिला नहीं है, जिसमें प्रति हजार आबादी पर एक-से-अधिक मलेरिया का प्रकरण हो।
- स्वास्थ्य विभाग द्वारा किये गए कार्य से प्रदेश को वर्ष 2015 में केटेगरी-3 के राज्यों से निकलकर केटेगरी-1 के राज्यों में स्थान मिला है।

मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक के महत्वपूर्ण निर्णय

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड के गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गए।

प्रमुख बिंदु

- मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिये एवं सतत् मार्गदर्शन से किसानों को प्रोत्साहन तथा सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र संगठन के रूप में 'मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड' गठन किये जाने का निर्णय लिया गया।
- बोर्ड में निगरानी एवं समीक्षा के लिये राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शीर्ष निकाय और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा।
- बोर्ड के राज्य परियोजना संचालक अपर मुख्य सचिव, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग और कार्यकारी संचालक, संचालक कृषि होंगे। बोर्ड का मुख्यालय भोपाल में होगा।
- जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में आत्मा गवर्निंग बोर्ड के निर्देशन में जिला परियोजना संचालक आत्मा द्वारा योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में गेहूँ एवं धान के रकबे तथा उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने, समर्थन मूल्य पर उपार्जन के खर्च में वृद्धि और इन फसलों के कारण प्रदेश में पर्यावरण असंतुलन की स्थिति निर्मित होने के मद्देनजर मध्य प्रदेश फसल विविधीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया।

- योजना के प्रस्ताव अनुसार आवेदक कंपनी/संस्था से प्राप्त प्रस्तावों को संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा परीक्षण कर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा के बाद निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति (CCIP) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
- योजना में स्वीकृत प्रस्तावों का क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग संचालक, किसान-कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा किया जाएगा।
- योजना में गेहूँ और धान के स्थान पर बोई जाने वाली गैर एम.एस.पी. फसलों को कवर किया जाएगा।
- इससे प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण-संरक्षण, जैव विविधता एवं टिकाऊ खेती संभव होगी। साथ ही, समर्थन मूल्य पर उपार्जन में कमी और दलहन-तिलहन के आयात पर निर्भरता कम होगी।
- मंत्रिपरिषद ने 'घुमंतू और अर्द्धघुमंतू जनजाति विभाग' का नाम बदलकर 'विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू कल्याण विभाग' करने हेतु मध्य प्रदेश कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया।
- इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने दतिया जिले में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना किये जाने तथा नवीन पदों के सृजन की मंजूरी दी।

मध्य प्रदेश में मवेशी को सार्वजनिक स्थान पर खुला छोड़ने पर होगी कार्रवाई

चर्चा में क्यों ?

26 अप्रैल, 2022 को कैबिनेट द्वारा मध्य प्रदेश नगरपालिका विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2022 के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- इस अध्यादेश के तहत मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सड़क या सार्वजनिक स्थान पर जान-बूझकर या उपेक्षापूर्वक किसी मवेशी या अन्य पशु को छोड़ा या बांधा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति से एक हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित जुर्माना राशि 5,000 रुपए थी, किंतु मंत्रियों के सुझाव पर इसे 1,000 रुपए कर दिया गया।
- गौरतलब है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को खुला छोड़ने की बढ़ती समस्या को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अनेक याचिकाएँ दाखिल की गई थीं, जिन पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने राज्य सरकार को विचरण करने वाले बेसहारा पशुओं के संबंध में नियमित कार्रवाई तथा जुर्माने की राशि निर्धारित करने के निर्देश दिये थे।

इंदौर में तीन दिवसीय 'एमपी ऑटो-शो-2022'

चर्चा में क्यों ?

28 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश में ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिये इंदौर में तीन दिवसीय ऑटो एक्सपो 'मध्य प्रदेश ऑटो-शो-2022' का शुभारंभ हुआ। यह ऑटो-शो 30 अप्रैल तक सुपर कॉरिडोर एवं नैट्रैक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक, पीथमपुर में होगा।

प्रमुख बिंदु

- मध्य प्रदेश को ऑटोमोबाइल हब बनाने के लिये राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एम.पी.आई.डी.सी.) के माध्यम से इंदौर में इस तीन दिवसीय ऑटो-शो का आयोजन किया जा रहा है।
- शो का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में ऑटो सेक्टर को बढ़ावा देना है, जिससे प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के अवसर बढ़ सकें।
- ऑटो-शो में देश एवं विदेश की लगभग 100 बहुप्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल मैनुफैक्चरिंग एवं ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैनुफैक्चरिंग कंपनियाँ शामिल हो रही हैं। इन सभी कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा।
- इसमें सभी प्रकार के वाहन, जैसे- ई-ह्वीकल, ईंधनचलित पैसेंजर कार, कॉमर्शियल ह्वीकल, एग्रीकल्चरल ह्वीकल एवं अर्थमूविंग और कंस्ट्रक्शन ह्वीकल प्रदर्शित किये जाएंगे।
- इंदौर को स्वच्छता में नंबर वन बनाने वाले विशेष उपकरण, जिनका उपयोग नगर निगम इंदौर द्वारा किया जाता है, का प्रदर्शन भी ऑटो-शो में किया जाएगा। लगभग 10 ऑटो कंपनियों द्वारा ऑटो एक्सपो में अपने उत्पादों को लॉन्च किया जाएगा।

- मध्य प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिये आटो-शो में पृथक् से स्टार्टअप जोन बनाया गया है, जिसमें ऑटो सेक्टर से संबंधित विभिन्न स्टार्टअप को बिना किसी शुल्क के स्थान उपलब्ध कराया गया है।
- प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये ऑटो-शो में विभिन्न बैठकें, जैसे- बायर्स सेलर मीट, बिजनेस-टू-गवर्नमेंट मीट, बिजनेस-टू-बिजनेस मीट सहित विभिन्न सेक्टर पर सेशन होंगे, साथ ही प्रदेश की नीतियों से अतिथियों को अवगत कराया जाएगा।
- ऑटोशो-2022 के माध्यम से पीथमपुर में विकसित एशिया के सबसे बड़े ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नैट्रैक्स के बारे में विभिन्न ऑटो कंपनियों को जानकारी दी जाएगी। साथ ही, नैट्रैक्स में उपलब्ध सुविधाओं से किस प्रकार उनके व्यवसाय में टेस्टिंग सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है इसके बारे में अवगत कराया जाएगा।
- नैट्रैक्स ऑटो टेस्टिंग ट्रैक पीथमपुर पर सुपर कार एवं सुपर बाइक रैली, ड्रैग रेस, विभिन्न टेस्टिंग ट्रैक का डेमो एवं गो-कार्ट जैसे मनोरंजक आयोजन भी किये जाएंगे।

तेंदूपत्ता संग्रहण दर अब 3 हजार रुपए प्रति मानक बोरा

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश वन विभाग ने प्रदेश के 45 लाख तेंदूपत्ता संग्राहकों के लिये वर्ष 2022 संग्रहण काल के लिये तेंदूपत्ता संग्रहण दर 3 हजार रुपये प्रति मानक बोरा निर्धारित करने के आदेश जारी कर दिये।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल, 2022 को वन समितियों के सम्मेलन में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाए जाने की घोषणा की थी।
- वर्ष 2021 तक संग्रहण दर 2500 रुपए प्रति मानक बोरा थी। इस वर्ष 16.29 लाख मानक बोरा का लक्ष्य रखा गया है।
- मध्य प्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्रहण का कार्य राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जाता है। प्रदेश में 60 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों और 1066 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से यह संग्रहण किया जाता है।
- वर्तमान में प्रदेश में 45 लाख तेंदूपत्ता संग्राहक हैं। इनमें से 50 फीसदी से ज्यादा 23 लाख संग्राहक जनजाति वर्ग के हैं। इसी तरह 40 फीसदी महिला संग्राहक भी हैं।
- इस वर्ष तेंदूपत्ता संग्रहण की दर में बढ़ोतरी से संग्रहण कार्य में संलग्न संग्राहकों को 500 करोड़ रुपए का संग्रहण पारिश्रमिक मिलेगा। यह पिछले वर्ष की तुलना में 81 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पारिश्रमिक होगा, जो ग्रीष्म ऋतु में रोजगार के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराने में सहायक होगा।
- प्रबंध संचालक पुष्कर सिंह ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभांश की राशि भी वितरित की जाती है। इस वर्ष से शुद्ध लाभांश को 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत सीधे तेंदूपत्ता संग्राहकों को वितरित किये जाने का निर्णय पूर्व में लिया जा चुका है।

ऊर्जा विभाग और केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के बीच ऋण एवं अनुदान के लिये अनुबंध हस्ताक्षरित

चर्चा में क्यों ?

29 अप्रैल, 2022 को मध्य प्रदेश के ऊर्जा क्षेत्र को आधुनिक तकनीक से सुसज्जित कर उन्नत बनाने के लिये ऊर्जा विभाग ने केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण एवं अनुदान के लिये अनुबंध हस्ताक्षरित किया।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों- पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के लिये 1400 करोड़ रुपए के वित्तपोषण के लिये पृथक् ऋण अनुबंध, पृथक् अनुदान अनुबंध एवं प्रोजेक्ट अनुबंध हस्ताक्षरित किये गए।
- ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि इस वृहद् योजना में 1120 करोड़ रुपए का ऋण केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक देगा तथा शासन शेष 280 करोड़ रुपए की राशि ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराएगा।
- विद्युत सुधार के इन प्रयासों से मध्य प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के कार्यक्षेत्र में स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन जैसे कार्य किये जा सकेंगे।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने 23 दिसंबर, 2021 को केएफडब्ल्यू डेवलपमेंट बैंक जर्मनी के साथ ऋण अनुबंध एवं अनुदान अनुबंध हस्ताक्षरित किया था। मध्य प्रदेश शासन इसी अनुबंध के आधार पर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिये प्रयासरत् है।

दृष्टि
The Vision